

ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया

प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

बनाम

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(सिविल अपील सं. 4602/2024)

22 मार्च 2024

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, * भा.मु.न्या., न्या. जे. बी.

पारदीवाला और न्या. मनोज मिश्रा]

विचारार्थ मुद्दा

मामला उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश को बरकरार रखने से संबंधित है, जिसमें विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसमें अपीलकर्तागण-मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रत्यर्थी के खिलाफ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित एक लेख को हटाने का निर्देश दिया गया था, साथ ही उन्हें सुनवाई की अगली तिथि तक किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रत्यर्थी के संबंध में लेख

ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

v. ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड

पोस्ट, प्रसारित या प्रकाशित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

हेडनोट्स

मानहानि – मीडिया प्लेटफॉर्म और/या पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का वाद – अंतरिम राहत/अंतरिम व्यादेश – विचारण न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्तागण-मीडिया प्लेटफॉर्म, उसके संपादक और पत्रकारों को प्रत्यर्थी के खिलाफ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित लेख को हटाने का निर्देश देने वाला अंतरिम आदेश और उन्हें सुनवाई की अगली तिथि तक किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रत्यर्थी के संबंध में लेख पोस्ट करने, प्रसारित करने या प्रकाशित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया – उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया – शुद्धता:

अभिनिर्धारित: विचारण न्यायाधीश का आदेश वादी के मामले की प्रथम दृष्टया ताकत, सुविधा की दृष्टि से या अपूरणीय कठिनाई पर भी चर्चा नहीं करता है – विचारण न्यायाधीश को विश्लेषण करने की

आवश्यकता थी कि इस तरह का एकपक्षीय व्यादेश क्यों आवश्यक था - इस तरह का आदेश अनुचित सेंसरशिप के बराबर है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है - एक अनुचित आदेश के माध्यम से एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश की स्वीकृति, निश्चित रूप से उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है - संवैधानिक रूप से संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर व्यादेश के प्रभाव ने हस्तक्षेप की और अधिक आवश्यकता उत्पन्न कर दी - उच्च न्यायालय को *प्रथम दृष्टया* मूल्यांकन करना चाहिए था कि क्या व्यादेश के अनुदान के लिए परीक्षण तथ्यों के मूल्यांकन के बाद विधिवत स्थापित किया गया था - विचारण न्यायाधीश द्वारा की गई त्रुटि को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा कायम रखा गया - केवल यह दर्ज करना कि एक प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है, कि सुविधा की दृष्टि से व्यादेश की स्वीकृति के पक्ष में है और एक अपूरणीय क्षति का कारण होगा, मामले के तथ्यों पर दिमाग लगाने के बराबर नहीं होगा - इसके अभाव में, विचारण न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के एकल

ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

v. ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड

न्यायाधीश के आदेशों को अपास्त कर दिया जाता है। [अनुच्छेद 11-13]

मानहानि – मीडिया प्लेटफॉर्म और/या पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का वाद – अंतरिम राहत/अंतरिम व्यादेश – अनुदान – तीन गुना परीक्षण का आवेदन:

अभिनिर्धारित: तीन-गुना परीक्षण में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना, सुविधा और अपूरणीय क्षति या नुकसान का संतुलन स्थापित करना, अंतरिम राहत प्रदान करना शामिल है - यह परीक्षण मानहानि के वादों में अंतरिम व्यादेश की स्वीकृति पर समान रूप से लागू होता है - तीन गुना परीक्षण यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए, दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए और पत्रकारिता के लेखों के खिलाफ व्यादेश के मामले में, अक्सर जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए - अंतरिम राहत देते समय, न्यायालय को विस्तृत कारण प्रदान करना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए कि परीक्षण कैसे संतुष्ट है और उद्धृत पूर्व निर्णय मामले के तथ्यों पर कैसे लागू होते हैं

- साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और प्रतिष्ठा और निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है - पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की रक्षा करने के संवैधानिक आदेश को कम करके नहीं आंका जा सकता है, और न्यायालयों को पूर्व-परीक्षण अंतरिम व्यादेश देते समय सावधानी से चलना चाहिए - न्यायालयों को असाधारण मामलों को छोड़कर पूर्व-पक्षीय व्यादेश नहीं देना चाहिए, जहां प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया बचाव निस्संदेह परीक्षण में विफल हो जाएगा - अन्य सभी मामलों में, सामग्री के प्रकाशन के विरुद्ध व्यादेश पूर्ण परीक्षण के पश्चात ही दी जानी चाहिए अथवा अपवादात्मक मामलों में, प्रत्यर्थी को अपनी प्रस्तुति रखने का अवसर दिए जाने के पश्चात ही दी जानी चाहिए। [अनुच्छेद 5, 7, 9]

वाद - 'एस.एल.ए.पी.पी. वाद' - की अवधारणा:

अभिनिर्धारित: 'एस.एल.ए.पी.पी.' शब्द का अर्थ 'सार्वजनिक भागीदारी के खिलाफ रणनीतिक मुकदमेबाजी' है - यह एक छत्र शब्द है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उन संस्थाओं द्वारा शुरू की

ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

v. ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड

गई मुकदमेबाजी को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो मीडिया या नागरिक समाज के सदस्यों के खिलाफ अपार आर्थिक शक्ति का उपयोग करते हैं, ताकि जनता को जनहित में महत्वपूर्ण मामलों के बारे में जानने या भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सके – अंतरिम व्यादेश की स्वीकृति, विचारण शुरू होने से पहले, अक्सर प्रकाशित की जाने वाली सामग्री के लिए 'मौत की सजा' के रूप में कार्य करता है, आरोपों के साबित होने से पहले - मानहानि के वादों में तदर्थ-अंतरिम व्यादेश देते समय, मुक्त भाषण और सार्वजनिक भागीदारी को प्रतिबंधित करने के लिए लंबे समय तक मुकदमेबाजी का उपयोग करने की क्षमता को भी न्यायालयों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। [पैरा 10]

उद्धृत निर्णयज विधि

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर

कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड [\[1996\]](#)

[पूरक 2 एस.सी.आर. 295](#): (1996) 4

एस.सी.सी. 622; *मॉर्गन स्टेनली म्यूचुअल*

फंड बनाम कार्तिक दास [\[1994\] पूरक 1 एस.सी.आर. 136](#): (1994) 4 एस.सी.सी. 225; आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य [\[1994\] पूरक 4 एस.सी.आर. 353](#): (1994) 6 एस.सी.सी. 632; रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अरविंदभाई रामभाई पटेल [\[2006\] पूरक 5 एस.सी.आर. 521](#): (2006) 8 एस.सी.सी. 726; श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड [\[2022\] 3 एस.सी.आर. 1173](#): (2023) 1 एस.सी.सी. 634 - संदर्भित।

बोनाई बनाम पेरीमैन [\(1891\) 95 ऑल ईआर 965](#); होली बनाम स्मिथ [\(1998\) 1 ऑल ईआर 853](#); फ्रेजर बनाम इवांस (1969) 1 क्यू.बी. 349 - संदर्भित।

उद्धृत पुस्तकें और पत्रिकाएं

डोनसन, एफ.जे.एल. 2000। लीगल इंटीमिडेशन: ए एस.एल.ए.पी.पी. इन द फेस ऑफ डेमोक्रेसी। लंदन, न्यूयॉर्क: फ्री एसोसिएशन बुक्स - संदर्भित।

ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

v. ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।

मुख्य शब्दों की सूची

मीडिया प्लेटफॉर्म; ऑनलाइन प्लेटफॉर्म; मानहानि;
मानहानि के वाद; अंतरिम राहत/अंतरिम व्यादेश;
प्रथम दृष्टया मामला; सुविधा का संतुलन; अपूरणीय
कठिनाई; एकपक्षीय व्यादेश; अंतरिम व्यादेश;
अनुचित सेंसरशिप; विवेकाधीन शक्ति; अनुचित
आदेश; मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ मानहानि की
कार्यवाही; व्यादेश; अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का
अधिकार; प्रतिष्ठा और गोपनीयता का अधिकार;
पत्रकारिता अभिव्यक्ति का संरक्षण; पूर्व-परीक्षण
अंतरिम व्यादेश; बोनार्ड मानक; लेखक की
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार; जनता को
जानने का अधिकार; 'एस.एल.ए.पी.पी. वाद'; 'जन
भागीदारी के खिलाफ रणनीतिक मुकदमेबाजी';
विलंबित विचारण।

से उत्पन्न मामला

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं.
4602/2024

आ.प्र.अ. सं. 79/2024 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च
न्यायालय के दिनांक 14.03.2024 के निर्णय और
आदेश से

पक्षकारों के लिए उपसंजातियां

मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल, डॉ. मेनका
गुरुस्वामी, वरि. अधिवक्तागण, रोहित कोचर, शिव
सपरा, समीरों बोरकाताकी, सुश्री रणजीत रोहतगी, रजत
गावा, इक्ष्वाकु मारवाह, विशाल सिंह, संस्कृति श्रीमाली,
केशव सहगल, ध्रुव शर्मा, राघव अग्रवाल, उत्कर्ष प्रताप,
लविश भंभानी, हर्षवर्धन ठाकुर, सुश्री सुवंगना अग्रवाल,
अपीलकर्तागण के लिए अधिवक्तागण।

महेश अग्रवाल, सुश्री माधवी अग्रवाल, शश्वत सिंह,
ई.सी.

अग्रवाल, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्तागण।

ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

v. ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड,

भा.मु.न्या.

1. अनुमति दी गई।
2. 01 मार्च 2024 को, दक्षिण साकेत न्यायालय, नई दिल्ली के अति.जि.न्या. 05 द्वारा¹ अपीलकर्तागण (एक मीडिया प्लेटफॉर्म, इसके संपादकों में से एक और संबंधित पत्रकारों) को एक सप्ताह के भीतर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित 21 फरवरी 2024 के एक लेख को हटाने का निर्देश देते हुए एक पक्षीय विज्ञापन अंतरिम आदेश पारित किया गया था। अपीलकर्तागण को सुनवाई की अगली तिथि तक किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रत्यर्थी-वादी के संबंध में लेख पोस्ट करने, प्रसारित करने या प्रकाशित करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था।

¹ "विचारण न्यायाधीश"

3. विचारण न्यायाधीश का आदेश इंगित करता है कि चर्चा, प्रत्यर्थी की प्रस्तुति को दर्ज करने के बाद, पैराग्राफ 7 पर शुरू होती है। विचारण न्यायाधीश के आदेश में पाया जाने वाला एकमात्र तर्क पैराग्राफ 8-9 में है, जो इस प्रकार है:

"8. मैंने यह डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी (पूर्वोक्त), चन्द्र कोचर (पूर्वोक्त), स्वामी रामदेव (पूर्वोक्त) में देखा है,

एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश पारित किया गया, यह देखते हुए कि विचाराधीन सामग्री की विषय-वस्तु स्वयं में मानहानिकारक थी।

9. मेरे विचार में, वादी ने व्यादेश के अंतरिम एकपक्षीय आदेश पारित करने के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया है, सुविधा की दृष्टि से भी वादी के पक्ष में है और प्रतिवादी के खिलाफ है और वादी को अपूरणीय क्षति और चोट हो सकती है, यदि प्रार्थना के अनुसार व्यादेश स्वीकार नहीं किया जाता। इसके मद्देनजर, प्रतिवादी सं. 1 और प्रतिवादी सं. 2 को इस आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दिनांक

ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

v. ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड

21.02.2024 (वादी के दस्तावेज का पृष्ठ 84 से 86) के लेख को हटाने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादीगण को सुनवाई की अगली तिथि तक किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर वादी के संबंध में उपरोक्त लेख को पोस्ट, प्रसारित या प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

4. विचारण न्यायाधीश के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दिनांक 14 मार्च 2024 के आदेश से बरकरार रखा है।² ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को अपील की विचारणीयता के बारे में संदेह था, लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश XLIII के प्रावधानों के संबंध में उस बिंदु पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।
5. अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए (i) *प्रथम दृष्टया* मामला, (ii) सुविधा का संतुलन और (iii) अपूरणीय क्षति या नुकसान स्थापित करने का तीन गुना परीक्षण, इस

² "आक्षेपित आदेश"

न्यायालय के न्यायशास्त्र में सुस्थापित है। यह परीक्षण मानहानि के वादों में अंतरिम व्यादेश देने पर समान रूप से लागू होता है। हालांकि, इस तीन गुना परीक्षण को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए,³ दूसरे पक्ष की हानि के लिए और पत्रकारिता के हिस्सों के खिलाफ व्यादेश के मामले में, अक्सर जनता की हानि के लिए। अंतरिम राहत देते समय, न्यायालय को विस्तृत कारण प्रदान करना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए कि तीन गुना परीक्षण कैसे संतुष्ट है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियों और उदाहरणों का एक सरसरी पुनरुत्पादन पर्याप्त नहीं है। न्यायालय को यह बताना चाहिए कि परीक्षण कैसे संतुष्ट है और उद्धृत पूर्व निर्णय मामले के तथ्यों पर कैसे लागू होती हैं।

6. इस बार-बार दोहराए जाने वाले परीक्षण के अलावा, कुछ अतिरिक्त कारक भी हैं, जिन पर न्यायालयों को एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश स्वीकृत समय विचार करना चाहिए। इनमें से कुछ कारकों को [मॉर्गन स्टेनली म्यूचुअल फंड बनाम कार्तिकदास](#)⁴ में इस न्यायालय की

³ दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड, [1996] पूरक 2 एससीआर 295: (1996) 4 एससीसी 622, के लिए 38.

⁴ 1 एससीआर 136: (1994) 4 एससीसी 225।

ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

v. ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड

तीन-न्यायाधीश की न्यायपीठ ने निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया था:

"36. सिद्धांत रूप में, एकपक्षीय व्यादेश केवल असाधारण परिस्थितियों में स्वीकृत किया जा सकता है। एकपक्षीय व्यादेश प्रदान करते समय न्यायालय को जिन कारकों पर विचार करना चाहिए वे हैं-

- (अ) क्या वादी को अपूरणीय या गंभीर क्षति होगी;
- (आ) क्या एकपक्षीय व्यादेश की स्वीकृति से इनकार करने में इसके अनुदान की तुलना में अधिक अन्याय शामिल होगा;
- (इ) न्यायालय उस समय पर भी विचार करेगा जब वादी को शिकायत किए गए कृत्य की पहली बार जानकारी मिली थी ताकि उसकी अनुपस्थिति में किसी पक्षकार के खिलाफ अनुचित आदेश देने से प्रतिबंधित किया जा सके;

- (ई) न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि क्या वादी ने कुछ समय के लिए उपमत्त व्यक्त किया था और ऐसी परिस्थितियों में यह एकपक्षीय व्यादेश नहीं देगा;
- (उ) न्यायालय यह अपेक्षा करेगा कि एकपक्षीय व्यादेश के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार आवेदन करते समय अत्यंत सद्भावना प्रदर्शित करेगा।
- (ऊ) यहां तक कि अगर स्वीकार किया जाता है, तो एकपक्षीय व्यादेश सीमित अवधि के लिए होगा।
- (ऋ) प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन और अपूरणीय क्षति जैसे सामान्य सिद्धांतों पर भी न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा।
7. महत्वपूर्ण बात यह है कि मीडिया प्लेटफार्मों और/या पत्रकारों द्वारा मानहानि से संबंधित वादों में, प्रतिष्ठा और गोपनीयता के अधिकार के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को संतुलित करने के अतिरिक्त विचार को ध्यान में रखा जाना चाहिए।⁵

⁵ आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य, [1994] पूरक. 4 एससीआर 353: (1994) 6 एससीसी 632.

ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

v. ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड

पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की रक्षा के संवैधानिक जनादेश को कम करके नहीं आंका जा सकता है, और न्यायालयों को पूर्व-विचारण अंतरिम व्यादेश देते समय सावधानी से चलना चाहिए। अनुसरण किए जाने वाले मानक को बोनार्ड बनाम पेरीमैन में निर्णय से लिया जा सकता है।⁶ अपीलीय न्यायालय (इंग्लैंड और वेल्स) द्वारा निर्धारित इस मानक को 'बोनार्ड मानक' नाम दिया गया है, जिसने मानहानि के वादों में अंतरिम व्यादेश की स्वीकृति के लिए एक सामान्य विधिक सिद्धांत का दर्जा प्राप्त कर लिया है।⁷ बोनार्ड (पूर्वोक्त) में अपीलीय न्यायालय ने निम्नलिखित अभিনিर्धारित किया:

"... लेकिन यह स्पष्ट है कि मानहानि के लिए कार्रवाई का विषय-वस्तु इतना विशेष है कि प्रत्याशित गलत को रोकने के लिए कार्रवाई के विचारण से पहले व्यादेश द्वारा हस्तक्षेप करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय असाधारण सावधानी की आवश्यकता होती है।

⁶ (1891) 95 ऑल ईआर 965।

⁷ होली बनाम स्मिथ, (1998) 1 ऑल ईआर 853।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वह है जो सार्वजनिक हित के लिए है जो व्यक्तियों के पास होना चाहिए, और वास्तव में, उन्हें बिना किसी बाधा के प्रयोग करना चाहिए, जब तक कि कोई गलत कार्य नहीं किया जाता है; और, जब तक एक कथित परिवाद असत्य नहीं है, तब तक कुछ गलत नहीं किया जाता है; लेकिन, इसके विपरीत, अक्सर एक कथित परिवाद के प्रकाशन और पुनरावृत्ति में एक बहुत ही स्वस्थ कार्य किया जाता है। जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि एक कथित परिवाद असत्य है, यह स्पष्ट नहीं है कि किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया गया है; और मुक्त अभिव्यक्ति को निर्बाध छोड़ने का महत्व मानहानि के मामलों में अंतरिम व्यादेश देने के साथ सबसे अधिक सावधानी और सतर्कता से निपटने का एक मजबूत कारण है।

(महत्व सन्निविष्ट)

ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

v. ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड

8. फ्रेजर बनाम इवांस में, ⁸अपीलीय न्यायालय ने बोनार्ड सिद्धांत का पालन किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"... जहां तक लेख श्री फ्रेजर के लिए मानहानिकारक होगा, यह स्पष्ट है कि वह व्यादेश प्राप्त नहीं कर सकता है। न्यायालय किसी लेख के प्रकाशन पर अवरोध नहीं लगाएगा, भले ही वह मानहानिकारक हो, जब प्रतिवादी कहता है कि वह इसे सही ठहराने या सार्वजनिक हित के मामले पर निष्पक्ष टिप्पणी करने का इरादा रखता है। यह तब से कई वर्षों से स्थापित है (बोनार्ड बनाम फेरीमैन, 1891, 2, अध्याय 269)। "कभी-कभी दिया गया कारण यह है कि औचित्य और निष्पक्ष टिप्पणी का बचाव जूरी के लिए है, जो संवैधानिक न्यायाधिकरण है, न कि न्यायाधीश के लिए। लेकिन एक बेहतर कारण यह है कि जनहित में सच्चाई सामने आनी चाहिए। ..."

⁸ [1969] 1 क्यू.बी 349।

(महत्त्व सन्निविष्ट)

9. संक्षेप में, किसी लेख के प्रकाशन के खिलाफ पूर्व-विचारण व्यादेश की स्वीकृति से लेखक के बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार और जनता के जानने के अधिकार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। एक व्यादेश, विशेष रूप से एकपक्षीय, यह स्थापित किए बिना नहीं दिया जाना चाहिए कि प्रतिबंधित करने की मांग की गई सामग्री 'दुर्भावनापूर्ण' या 'स्पष्ट रूप से गलत' है। विचारण शुरू होने से पहले, लापरवाही से अंतरिम व्यादेश देने से सार्वजनिक बहस का गला घोट दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालयों को असाधारण मामलों को छोड़कर एकपक्षीय व्यादेश नहीं देना चाहिए, जहां प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया बचाव निस्संदेह विचारण में विफल हो जाएगा। अन्य सभी मामलों में, सामग्री के प्रकाशन के खिलाफ व्यादेश केवल एक पूर्ण विचारण आयोजित किए जाने के बाद या असाधारण मामलों में, प्रत्यर्थी को अपनी प्रस्तुतियाँ करने का मौका दिए जाने के बाद ही दी जानी चाहिए।
10. विभिन्न न्यायक्षेत्रों में, 'एस.एल.ए.पी.पी. वाद' की अवधारणा को या तो विधि द्वारा या न्यायालयों द्वारा मान्यता दी गई है। 'एस.एल.ए.पी.पी.' शब्द का अर्थ

ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

v. ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड

'सार्वजनिक भागीदारी के खिलाफ रणनीतिक मुकदमेबाजी' है और यह एक छत्र शब्द है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उन संस्थाओं द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो मीडिया या नागरिक समाज के सदस्यों के खिलाफ अपार आर्थिक शक्ति का उपयोग करते हैं, ताकि जनता को जानने या भाग लेने से रोका जा सके।⁹ हमें विलंबित विचारणों की वास्तविकताओं से अवगत होना चाहिए। मुकदमा शुरू होने से पहले अंतरिम निषेधाज्ञा का प्रावधान, अक्सर आरोप साबित होने से पहले ही प्रकाशित की जाने वाली सामग्री के लिए 'मृत्युदंड' के रूप में कार्य करता है। मानहानि के वादों में अंतरिम व्यादेश देते समय, मुक्त अभिव्यक्ति और सार्वजनिक भागीदारी को रोकने के लिए विलंबित मुकदमेबाजी का उपयोग करने की क्षमता को भी न्यायालयों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

11. विचारण न्यायाधीश के आदेश में वादी के मामले की प्रथम दृष्टया मजबूती पर सरसरी तौर पर भी चर्चा नहीं

⁹ डोनसन, एफ.जे.एल. 2000। लीगल इंटीमिडेशन: ए एस.एल.ए.पी.पी. इन द फेस ऑफ़ डेमोक्रेसी। लंदन, न्यूयॉर्क: फ्री एसोसिएशन बुक्स।

की गई है, न ही इसमें सुविधा के संतुलन या होने वाली अपूरणीय कठिनाई का जिक्र किया गया है। विचारण न्यायाधीश के समक्ष किए गए तथ्यात्मक आधार और प्रत्यर्थी की दलीलों को निर्धारित करने के बाद, विचारण न्यायाधीश को विश्लेषण करने की आवश्यकता थी कि इस तरह का एकपक्षीय व्यादेश क्यों आवश्यक था। विचारण न्यायाधीश ने पैरा 7-8 में केवल यह कहा है कि न्यायालय ने "आज तक उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया है" और कुछ उदाहरणों पर ध्यान दिया है जहां एक अंतरिम व्यादेश दिया गया था। वाद के गुण-दोष पर सरसरी तौर पर विचार किए बिना, विचारण न्यायाधीश द्वारा दिया गया अंतरिम व्यादेश अनुचित सेंसरशिप के बराबर है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

12. निस्संदेह, अंतरिम व्यादेश देना विवेकाधीन शक्ति का एक अभ्यास है और अपीलीय न्यायालय (इस मामले में, उच्च न्यायालय) आमतौर पर अंतरिम राहत देने में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि, पूर्व निर्णय को देखते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलीय न्यायालयों को अंतरिम राहत प्रदान करने में हस्तक्षेप करना चाहिए यदि विवेक का प्रयोग "*मनमाने*

ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

v. ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड

ढंग से, स्वेच्छाचारी ढंग से, विकृत रूप से किया गया हो, या जहाँ न्यायालय ने अंतरिम व्यादेश प्रदान करने या अस्वीकार करने को विनियमित करने वाले विधि के स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की हो।¹⁰ एक अनुचित आदेश के माध्यम से एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश की स्वीकृति, निश्चित रूप से उपरोक्त सूत्रीकरण के अंतर्गत आता है, जिससे उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यह एक मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही में दिए गए व्यादेश का मामला है, इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार पर व्यादेश के प्रभाव ने हस्तक्षेप को और आवश्यक बना दिया।

13. उपरोक्त के मद्देनजर, उच्च न्यायालय को, हमारे विचार में, कम से कम *प्रथम दृष्टया* यह भी आकलन करना चाहिए था कि क्या व्यादेश देने के लिए परीक्षण, तथ्यों के मूल्यांकन के बाद विधिवत स्थापित किया गया था। विचारण न्यायाधीश द्वारा की गई वही त्रुटि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा की गई है। केवल

¹⁰ रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अरविंदभाई रामभाई पटेल, [2006] प्रक 5 एससीआर 521: (2006) 8 एससीसी 726, के लिए 128; श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, [2022] 3 एससीआर 1173: (2023) 1 एससीसी 634, पैरा 37.

यह दर्ज करना कि एक *प्रथम दृष्टया* मामला मौजूद है, कि सुविधा का संतुलन व्यादेश की स्वीकृति के पक्ष में है और यह कि एक अपूरणीय क्षति होगी, मामले के तथ्यों पर दिमाग लगाने योग्य नहीं होगी। तीन गुना परीक्षण को केवल उन तथ्यों को देखे बिना एक मंत्र के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता है जिनके आधार पर व्यादेश मांगा गया था। विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के विचार के अभाव में, हमारे पास विचारण न्यायाधीश के दिनांक 1 मार्च 2024 और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के दिनांक 14 मार्च 2024 के दोनों आदेशों को अपास्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम तदनुसार ऐसा करते हैं।

14. चूंकि कार्यवाही अब 26 मार्च 2024 को विचारण न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि प्रत्यर्थीगण के लिए व्यादेश के लिए अपने आवेदन को नवीनीकृत करना खुला होगा, जिस पर विचारण न्यायाधीश पक्षकारों को सुनने के बाद नए आदेश पारित करेंगे और उन टिप्पणियों को ध्यान में रखेंगे जो निर्णय और आदेश के उपरोक्त खंड में निहित हैं। इस संबंध में पक्षकारों के सभी अधिकार और विवाद

ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

v. ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड

खुले रखे गए हैं। इस घटना में कि अपीलकर्ता व्यादेश के लिए आवेदन को चुनौती देना चाहते हैं, वे सूचीबद्ध की अगली तिथि से पहले विचारण न्यायाधीश के समक्ष अपना जवाब दाखिल करेंगे।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्णय और आदेश के उपरोक्त खंड को वर्तमान मामले की योग्यता पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त खंड का उद्देश्य अंतरिम व्यादेश के लिए आवेदन पर सुनवाई करते समय ध्यान में रखे जाने वाले व्यापक मापदंडों को प्रदान करना है।
16. तदनुसार, अपील का निपटान उपर्युक्त शर्तों में किया जाता है।
17. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान कर दिया गया है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट्स: निधि जैन

मामले का परिणाम:

अपील का निपटान कर दिया गया।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.